SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

हमास और इज़राइलः अस्मिता, संघर्ष और भू–राजनीति के चौराहे पर एक ऐतिहासिक विश्लेषण एक गहन राजनीतिक विज्ञान

अनामिका, पी.–एच.डी., राजनीति विज्ञान विभाग
एस.बी. कॉलेज, आरा, बिहार, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Author
अनामिका, पी.–एच.डी.
E-mail : anamikaavinashakashavani@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 23/05/2025
Revised on : 24/07/2025
Accepted on : 02/08/2025
Overall Similarity : 05% on 25/07/2025

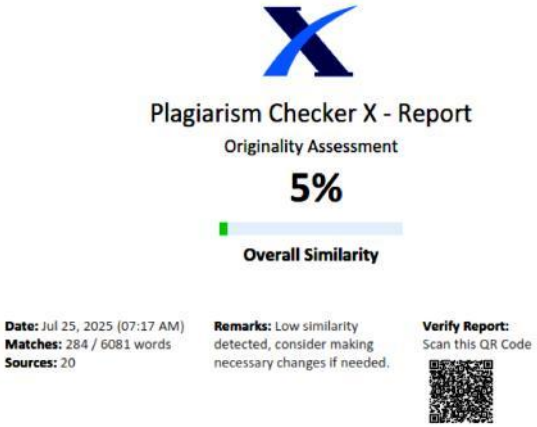

शोध सार

यह शोध आलेख हमास और इज़राइल के मध्य चले आ रहे बहुआयामी और गहरे संघर्ष का एक व्यापक राजनीतिक विज्ञान विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य सतही विमर्श से परे जाकर उन ऐतिहासिक, वैचारिक, भू–राजनीतिक और सामाजिक–आर्थिक कारकों की गहन पड़ताल करना है जो इस टकराव को निरंतर ऊर्जा प्रदान करते हैं। 19वीं सदी के अंत में ज़ायोनी आंदोलन के उदय से लेकर 1948 में इज़राइल राज्य की स्थापना, 1967 के छह–दिवसीय युद्ध, पहले और दूसरे इंतिफादा, और 1987 में हमास के गठन तक की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण करते हुए, यह लेख संघर्ष के विकासक्रम को रेखांकित करता है। इसमें हमास की वैचारिक जड़ों, उसके दोहरे चरित्र (एक सशस्त्र प्रतिरोध समूह और एक प्रशासनिक इकाई के रूप में), और उसके राजनीतिक लक्ष्यों की विस्तृत विवेचना की गई है। इसके समानांतर, इज़राइल की सुरक्षा नीति, उसकी राजनीतिक व्यवस्था के भीतर के अंतर्विरोधों, और क्षेत्रीय आधिपत्य की उसकी रणनीतियों का भी आलोचनात्मक मूल्यांकन किया गया है। यह आलेख भूमि विवाद, यरूशलेम की स्थिति, शरणार्थियों की वापसी का अधिकार, और गाजा की नाकाबंदी जैसे केंद्रीय मुद्दों को संघर्ष के मूल में रखता है। इसके अतिरिक्त, यह संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान, मिस्र और अन्य अरब देशों जैसे अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अभिनेताओं की भूमिका और उनके हस्तक्षेप के प्रभावों का भी विश्लेषण करता है। अंत में, यह शोध स्थायी शांति की राह में आने वाली चुनौतियों, दो–राज्य समाधान की वर्तमान प्रासंगिकता, और भविष्य के संभावित परिदृश्यों पर एक गंभीर विमर्श प्रस्तुत करता है। इस अध्ययन में अकादमिक शोध, ऐतिहासिक दस्तावेज़ों, नीति–पत्रों और विभिन्न दृष्टिकोणों वाले मीडिया स्रोतों का उपयोग किया

गया है ताकि एक संतुलित और ज्ञानवर्धक विश्लेषण प्रदान किया जा सके।

मुख्य शब्द

इज़राइल, हमास, राष्ट्रीय अस्मिता, धार्मिक विश्वास, राजनीतिक, संघर्ष.

परिचय और ऐतिहासिक पष्ठभूमि

1. प्रस्तावनाः एक अनसुलझी पहेली

इज़राइल–फिलिस्तीन संघर्ष, और विशेष रूप से हमास और इज़राइल के बीच का टकराव, समकालीन विश्व की सबसे जटिल और विस्फोटक भू–राजनीतिक समस्याओं में से एक है। यह केवल दो पक्षों के बीच का क्षेत्रीय विवाद नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय अस्मिता, धार्मिक विश्वास, ऐतिहासिक अन्याय, और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन की एक बहुस्तरीय गाथा है। दशकों से, यह संघर्ष अनगिनत युद्धों, हिंसक झड़पों, कूटनीतिक विफलताओं और मानवीय त्रासदियों का कारण बना है। समाचारों की सुर्खियों में अक्सर रॉकेट हमलों, हवाई बमबारियों और हताहतों के आंकड़ों का ज़िक्र होता है, लेकिन इन घटनाओं के पीछे छिपे गहरे राजनीतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक कारण अक्सर अनदेखे रह जाते हैं।

यह शोध आलेख इसी गहराई में उतरने का एक प्रयास है। इसका उद्देश्य हमास और इज़राइल के संघर्ष को एक राजनीतिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य से समझना है, जिसमें दोनों पक्षों के आख्यानों, उनकी रणनीतियों, उनकी कमजोरियों और उनके लक्ष्यों का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण शामिल हो। क्या यह संघर्ष केवल धर्म के नाम पर है? या यह भूमि और संसाधनों पर नियंत्रण की लड़ाई है? क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस आग को बुझाने में सहायक रहा है या उसने इसे और भड़काया है? इन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए, हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा और उन घटनाओं को समझना होगा जिन्होंने इस क्षेत्र के वर्तमान स्वरूप को गढ़ा है।

2. ऐतिहासिक जड़ें: ज़ायोनीवाद से ब्रिटिश मैंडेट तक

संघर्ष की जड़ें 19वीं सदी के अंत में यूरोप में जन्मे ज़ायोनी आंदोलन (Zionist Movement) में खोजी जा सकती हैं। थियोडोर हर्ज़ल जैसे विचारकों के नेतृत्व में, इस आंदोलन का लक्ष्य यहूदियों के लिए उनके ऐतिहासिक 'वादा किए गए देश' (Promised Land) – यानी फिलिस्तीन – में एक संप्रभु राष्ट्र की स्थापना करना था। उस समय फिलिस्तीन ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था और यहाँ सदियों से अरब आबादी, जिसमें मुस्लिम, ईसाई और एक छोटा यहूदी समुदाय शामिल था, निवास करती थी।

प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य की हार के बाद परिदृश्य नाटकीय रूप से बदल गया। 1917 में, ब्रिटेन ने बाल्फोर घोषणा (Balfour Declaration) जारी की, जिसमें फिलिस्तीन में ''यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय घर'' की स्थापना का समर्थन किया गया। इस घोषणा ने अरब जगत में आक्रोश की लहर पैदा कर दी, जिन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। युद्ध के बाद, फिलिस्तीन को ब्रिटिश मैंडेट (British Mandate for Palestine) के तहत रखा गया, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र को स्व–शासन के लिए तैयार करना था।

ब्रिटिश मैंडेट का काल (1920–1948) यहूदी आप्रवासन में भारी वृद्धि और अरब–यहूदी तनाव के बढ़ने का गवाह बना। ज़ायोनी संगठन भूमि खरीद रहे थे, अपनी राजनीतिक और सैन्य संस्थाएँ (जैसे हगाना) बना रहे थे, जबकि फिलिस्तीनी अरब अपनी ज़मीन और पहचान खोने के डर से आंदोलित हो रहे थे। 1936–1939 का अरब विद्रोह इस बढ़ते तनाव का एक हिंसक प्रकटीकरण था।

3. 1948 का युद्ध और इज़राइल राज्य का जन्म

द्वितीय विश्व युद्ध और होलोकॉस्ट (Holocaust) की भयावहता ने यहूदी राष्ट्र की मांग को और बल दिया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में, संयुक्त राष्ट्र ने 1947 में फिलिस्तीन के विभाजन के लिए एक योजना (UN Partition Plan for Palestine] Resolution 181) प्रस्तावित की, जिसमें क्षेत्र को एक अरब राज्य, एक यहूदी राज्य और यरूशलेम के लिए

एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय शासन में विभाजित करने की सिफारिश की गई थी। यहूदी नेतृत्व ने इस योजना को स्वीकार कर लिया, लेकिन अरब नेताओं और देशों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया।

14 मई 1948 को, जैसे ही ब्रिटिश मैंडेट समाप्त हुआ, डेविड बेन–गुरियन ने इज़राइल राज्य की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अगले ही दिन, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इराक की सेनाओं ने इज़राइल पर आक्रमण कर दिया। यह 1948 का अरब–इज़राइली युद्ध था। युद्ध के अंत में, इज़राइल विजयी हुआ और उसने संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र से कहीं अधिक भूमि पर नियंत्रण कर लिया। जॉर्डन ने वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर कब्ज़ा कर लिया, जबकि मिस्र ने गाजा पट्टी पर नियंत्रण स्थापित किया।

इस युद्ध का सबसे विनाशकारी परिणाम था ''नकबा'' (Nakba), जिसका अरबी में अर्थ है ''आपदा''। लगभग 750,000 फिलिस्तीनी अरब अपने घरों से विस्थापित हो गए और पड़ोसी देशों में शरणार्थी बन गए। उनकी भूमि और संपत्तियाँ इज़राइल द्वारा जब्त कर ली गईं। यह विस्थापन और शरणार्थियों की वापसी का अधिकार (Right of Return) आज भी फिलिस्तीनी राष्ट्रीय आंदोलन और हमास की विचारधारा का एक केंद्रीय स्तंभ है।

4. 1967 का छह–दिवसीय युद्ध और कब्जे का युग

अगले दो दशक तनाव और सीमा पर झड़पों से भरे रहे। 1967 में, इज़राइल और उसके अरब पड़ोसियों (मिस्र, जॉर्डन और सीरिया) के बीच तनाव चरम पर पहुँच गया। 5 जून 1967 को, इज़राइल ने एक पूर्व–emptive हवाई हमला किया, जिसने मिस्र की वायु सेना को ज़मीन पर ही नष्ट कर दिया। मात्र छह दिनों में, इज़राइल ने मिस्र से गाजा पट्टी और सिनाई प्रायद्वीप, जॉर्डन से वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम, और सीरिया से गोलान हाइट्स पर कब्ज़ा कर लिया।

1967 का छह–दिवसीय युद्ध मध्य पूर्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। सने इज़राइल को एक प्रमुख क्षेत्रीय सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। लेकिन इसके साथ ही इसने कब्जे (Occupation) के एक नए युग की शुरुआत की। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में रहने वाले लाखों फिलिस्तीनी अब इज़राइली सैन्य शासन के अधीन आ गए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 242 पारित किया, जिसमें इज़राइल से कब्जे वाले क्षेत्रों से हटने का आह्वान किया गया, लेकिन यह प्रस्ताव आज तक पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। इस कब्जे ने फिलिस्तीनी राष्ट्रवाद को और तीव्र किया और सशस्त्र प्रतिरोध के नए रूपों को जन्म दिया, जिसकी परिणति अंततः हमास जैसे संगठनों के उदय में हुई।

हमास का उदय और वैचारिक आधार

1. हमास का उद्भवः मुस्लिम ब्रदरहुड से इंतिफादा तक

हमास, जिसका पूरा नाम ''हरकत अल–मुकावामा अल–इस्लामिया'' (Harakat al-Muqawama al-Islamiyya) है, का अर्थ ''इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन'' है। इसकी स्थापना दिसंबर 1987 में पहले इंतिफादा (First Intifada) की शुरुआत में शेख अहमद यासीन, अब्देल अज़ीज़ अल–रंतीसी और मोहम्मद ताहा द्वारा गाजा में की गई थी। इंतिफादा (अरबी में ''विद्रोह'' या ''उबाल'') इज़राइली कब्जे के खिलाफ एक स्वतःस्फूर्त फिलिस्तीनी विद्रोह था, जो पत्थर फेंकने वाले युवाओं और बड़े पैमाने पर नागरिक अवज्ञा के लिए जाना जाता है।

हमास की जड़ें मिस्र के मुस्लिम ब्रदरहुड (Muslim Brotherhood) आंदोलन की फिलिस्तीनी शाखा में हैं। 1987 से पहले, शेख यासीन और उनके सहयोगी मुख्य रूप से सामाजिक और धार्मिक कार्यों (दावा) पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, जैसे कि मस्जिदों, क्लीनिकों और स्कूलों का नेटवर्क बनाना। उन्होंने फिलिस्तीनी समाज का ष्इस्लामीकरणष करने को अपनी प्राथमिकता बनाया। हालांकि, पहले इंतिफादा के फैलते ही, उन्होंने महसूस किया कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी संगठनों जैसे कि यासर अराफात के फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (Palestine Liberation Organization - PLO) द्वारा चलाए जा रहे प्रतिरोध आंदोलन में एक वैचारिक शून्य था। उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाते हुए एक ऐसा संगठन बनाया जो इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित सशस्त्र प्रतिरोध की वकालत करता था।

2. 1988 का चार्टरः एक अपरिवर्तनीय विचारधारा?

अगस्त 1988 में, हमास ने अपना घोषणापत्र, जिसे हमास चार्टर के नाम से जाना जाता है, जारी किया। यह दस्तावेज़ संगठन की कट्टरपंथी और असम्बद्ध विचारधारा को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। चार्टर के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैंः

- **फिलिस्तीन एक इस्लामी वक्फ हैः** चार्टर घोषित करता है कि फिलिस्तीन की भूमि एक इस्लामी वक्फ (धार्मिक बंदोबस्ती) है, जिसे किसी भी अरब नेता या देश द्वारा त्यागा या सौंपा नहीं जा सकता। यह भूमि पीढ़ियों तक मुसलमानों की रहेगी।
- **इज़राइल का विनाशः** चार्टर स्पष्ट रूप से इज़राइल के अस्तित्व को नकारता है और उसके विनाश का आह्वान करता है। यह शांतिपूर्ण समाधान या बातचीत की किसी भी संभावना को खारिज करता है और जिहाद (पवित्र युद्ध) को फिलिस्तीन को ''मुक्त'' कराने का एकमात्र तरीका बताता है।
- **यहूदी–विरोधी तत्वः** चार्टर में कई जगहों पर यहूदी–विरोधी षड्यंत्र के सिद्धांत शामिल हैं, जो ''द प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ ज़ायन'' जैसे ग्रंथों का हवाला देते हैं और वैश्विक घटनाओं के लिए यहूदियों को दोषी ठहराते हैं।
- **पीएलओ की आलोचनाः** चार्टर पीएलओ के धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण की आलोचना करता है और फिलिस्तीनी मुद्दे को केवल एक राष्ट्रवादी समस्या के बजाय एक इस्लामी समस्या के रूप में प्रस्तुत करता है।

यह चार्टर लंबे समय तक हमास की पहचान का केंद्र बिंदु रहा और इसी के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और कई अन्य देशों ने इसे एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया।

3. 2017 का दस्तावेज़ः रणनीति में बदलाव या दिखावा?

लगभग तीन दशकों के बाद, मई 2017 में, हमास ने एक नया नीतिगत दस्तावेज़ जारी किया। इस दस्तावेज़ को कई विश्लेषकों ने हमास द्वारा अपनी छवि को नरम करने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ जुड़ने के प्रयास के रूप में देखा। 2017 के दस्तावेज़ में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव थेः

- **1967 की सीमाओं पर सहमतिः** यद्यपि यह अभी भी ऐतिहासिक फिलिस्तीन पर अपने दावे को नहीं छोड़ता, नया दस्तावेज़ 1967 की सीमाओं (वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी यरूशलेम) के आधार पर एक अंतरिम फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना को ''राष्ट्रीय सहमति का सूत्र'' मानता है। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव था, क्योंकि यह पहली बार था जब हमास ने दो–राज्य समाधान की दिशा में एक व्यावहारिक कदम को स्वीकार किया था, भले ही अस्थायी रूप से।
- **संघर्ष की प्रकृतिः** दस्तावेज़ ने संघर्ष को यहूदियों के साथ धार्मिक युद्ध के रूप में चित्रित करने से दूरी बनाई। इसने स्पष्ट किया कि हमास का संघर्ष ''ज़ायोनी परियोजना'' के खिलाफ है, न कि यहूदियों के खिलाफ क्योंकि वे यहूदी हैं। इसने 1988 के चार्टर के खुले यहूदी–विरोधी स्वर को कम करने का प्रयास किया।
- **मुस्लिम ब्रदरहुड से दूरीः** दस्तावेज़ में मुस्लिम ब्रदरहुड का कोई उल्लेख नहीं था, जो मिस्र जैसे देशों को एक संकेत था, जहाँ ब्रदरहुड को एक आतंकवादी संगठन माना जाता है।

हालांकि, इस दस्तावेज़ ने 1988 के चार्टर को औपचारिक रूप से रद्द नहीं किया। इसने इज़राइल को मान्यता देने से भी इनकार किया और सशस्त्र प्रतिरोध को एक वैध अधिकार के रूप में बनाए रखा इसलिए, आलोचकों का तर्क है कि यह केवल एक रणनीतिक पीआर अभ्यास था, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वैधता हासिल करना था, जबकि इसके मूल लक्ष्य अपरिवर्तित रहे। इज़राइल ने इसे ''दुनिया की आँखों में धूल झोंकने'' का प्रयास कहकर खारिज कर दिया।

4. हमास का दोहरा चरित्रः प्रतिरोध और शासन

हमास को समझने के लिए, उसके दोहरे चरित्र को पहचानना महत्वपूर्ण है। एक ओर, यह एक सशस्त्र

प्रतिरोध समूह है जो इज़राइल के खिलाफ रॉकेट हमले, आत्मघाती बम विस्फोट (विशेषकर दूसरे इंतिफादा के दौरान) और अन्य सैन्य कार्रवाइयां करता है। इसकी एक सैन्य शाखा है, इज्ज़ अद्–दीन अल–कसम ब्रिगेड (Izz ad&Din al-Qassam Brigades), जो इज़राइली सेना के साथ सीधे संघर्ष में शामिल है।

दूसरी ओर, 2006 के फिलिस्तीनी विधायी चुनावों में अपनी आश्चर्यजनक जीत के बाद, हमास गाजा पट्टी में प्रभावी प्रशासनिक इकाई बन गया है। 2007 में, फतह के साथ एक संक्षिप्त और हिंसक गृह युद्ध के बाद, हमास ने गाजा पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया तब से, यह लगभग 20 लाख फिलिस्तीनियों पर शासन कर रहा है। एक शासी निकाय के रूप में, हमास को नागरिक सेवाओं, कानून और व्यवस्था, और अर्थव्यवस्था को प्रबंधित करने की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह दोहरा चरित्र अक्सर विरोधाभासों को जन्म देता है। उदाहरण के लिए, इसे इज़राइल के साथ संघर्ष विराम (truce) पर बातचीत करनी पड़ती है ताकि गाजा में मानवीय सहायता आ सके, जबकि इसकी मूल विचारधारा इज़राइल के साथ किसी भी समझौते को खारिज करती है। यह शासन की व्यावहारिक आवश्यकताओं और प्रतिरोध की वैचारिक मांगों के बीच एक निरंतर संतुलन बनाने का कार्य है।

इज़राइल की सुरक्षा नीति और राजनीतिक परिदृश्य

1. सुरक्षा सिद्धांतः रक्षा, प्रतिरोध और पूर्व–emption

इज़राइल की स्थापना के दिन से ही, उसकी राष्ट्रीय नीति का केंद्र बिंदु सुरक्षा रहा है। चारों ओर से शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों से घिरा होने की भावना ने इसके सुरक्षा सिद्धांत को आकार दिया है। इज़राइल की सुरक्षा नीति के मुख्य स्तंभ हैं:

- **रक्षा (Defense):** इज़राइल ने अपनी रक्षा के लिए एक शक्तिशाली और तकनीकी रूप से उन्नत सेना, इज़राइल रक्षा बल (Israel Defense Forces - IDF) का निर्माण किया है। अनिवार्य सैन्य सेवा, एक मजबूत रक्षा उद्योग और अत्याधुनिक खुफिया एजेंसियां (जैसे मोसाद और शिन बेट) इसकी रक्षा क्षमताओं की रीढ़ हैं।
- **प्रतिरोध (Deterrence):** इज़राइल का उद्देश्य अपने दुश्मनों को उस पर हमला करने से रोकना है। यह अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करके और किसी भी हमले पर असमान रूप से शक्तिशाली प्रतिक्रिया देकर प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखता है। इसका अघोषित परमाणु हथियार कार्यक्रम भी इस प्रतिरोधक रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है।
- **पूर्व–emption (Pre-emption):** यदि इज़राइल को लगता है कि कोई आसन्न खतरा है, तो वह पहले हमला करने के सिद्धांत में विश्वास करता है। 1967 के छह–दिवसीय युद्ध की शुरुआत और 1981 में इराक के ओसिराक परमाणु रिएक्टर पर हवाई हमला इस सिद्धांत के प्रमुख उदाहरण हैं।
- **संघर्ष को दुश्मन के इलाके में ले जानाः** इज़राइल की रणनीति यथासंभव अपनी धरती पर युद्ध से बचना है और लड़ाई को दुश्मन के क्षेत्र में स्थानांतरित करना है।

हमास के संदर्भ में, इज़राइल की नीति मुख्य रूप से रोकथाम (Containment) और ''घास काटना'' (Mowing the lawn) की रही है। ''घास काटना'' एक अनौपचारिक शब्द है जिसका उपयोग समय–समय पर गाजा में हमास की सैन्य क्षमताओं को नष्ट करने के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाने की रणनीति का वर्णन करने के लिए किया जाता है, ताकि उसे एक निश्चित अवधि के लिए कमजोर किया जा सके। ऑपरेशन कास्ट लीड (2008–09), ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस (2012), और ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज (2014) ऐसे ही अभियानों के उदाहरण हैं।

2. गाजा की नाकाबंदीः एक विवादास्पद रणनीति

2007 में हमास द्वारा गाजा पर नियंत्रण करने के बाद, इज़राइल ने मिस्र के साथ मिलकर गाजा पट्टी की भूमि, वायु और समुद्री नाकाबंदी कर दी। इज़राइल का तर्क है कि यह नाकाबंदी हमास को हथियार और सामग्री प्राप्त करने से रोकने के लिए आवश्यक है, जिससे इज़राइली नागरिकों की सुरक्षा हो सके।

हालांकि, इस नाकाबंदी के विनाशकारी मानवीय परिणाम हुए हैं। इसने गाजा की अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया है, बेरोजगारी को चरम पर पहुंचा दिया है, और आबादी को मानवीय सहायता पर बहुत अधिक निर्भर बना दिया है। संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों ने इस नाकाबंदी को ''सामूहिक दंड'' (Collective Punishment) का एक रूप बताया है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। आलोचकों का तर्क है कि नाकाबंदी ने गाजा के लोगों को और अधिक कट्टरपंथी बनाया है और हमास के हाथों में एक शक्तिशाली प्रचार उपकरण प्रदान किया है। यह एक दुष्चक्र बनाता हैः इज़राइल सुरक्षा कारणों से नाकाबंदी बनाए रखता है, और नाकाबंदी से उत्पन्न हताशा और गुस्सा हमास जैसे समूहों के लिए समर्थन बढ़ाता है, जिससे इज़राइल के लिए सुरक्षा खतरे और बढ़ जाते हैं।

3. इज़राइली राजनीति और फिलिस्तीनी प्रश्न

इज़राइल एक जीवंत लेकिन खंडित बहुदलीय लोकतंत्र है। फिलिस्तीनी प्रश्न और शांति प्रक्रिया का मुद्दा हमेशा से इज़राइली राजनीति में एक केंद्रीय विभाजन रेखा रहा है। मोटे तौर पर, इज़राइली राजनीतिक स्पेक्ट्रम को तीन खेमों में बांटा जा सकता हैः

- **दक्षिणपंथी (Right-wing)**: लिकुड पार्टी और उससे भी अधिक दक्षिणपंथी धार्मिक ज़ायोनी पार्टियां इस खेमे का नेतृत्व करती हैं। वे एक मजबूत, अविभाजित यरूशलेम और वेस्ट बैंक (जिसे वे यहूदिया और सामरिया कहते हैं) पर इज़राइली संप्रभुता का समर्थन करते हैं। वे सुरक्षा पर जोर देते हैं और फिलिस्तीनियों को रियायतें देने के प्रति अत्यधिक शंकालु होते हैं। वेस्ट बैंक में इज़राइली बस्तियों का विस्तार उनकी नीति का एक प्रमुख हिस्सा है। वे अक्सर हमास के साथ किसी भी तरह की बातचीत का विरोध करते हैं और सैन्य कार्रवाई को एकमात्र समाधान मानते हैं।
- **केंद्र (Center)**: येश अतीद और ब्लू एंड व्हाइट जैसी पार्टियां केंद्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे सुरक्षा के मुद्दों पर मजबूत रुख अपनाते हैं, लेकिन साथ ही दो–राज्य समाधान के विचार के लिए अधिक खुले हो सकते हैं, बशर्ते इज़राइल की सुरक्षा की गारंटी हो। वे आमतौर पर एक अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हैं।
- **वामपंथी (Left-wing)**: लेबर पार्टी और मेरेत्ज़ जैसी पार्टियां पारंपरिक रूप से वामपंथी खेमे में हैं। वे फिलिस्तीनियों के साथ शांति समझौते और दो–राज्य समाधान के सबसे मजबूत समर्थक हैं। वे बस्तियों के विस्तार की आलोचना करते हैं और कब्जे को समाप्त करने की वकालत करते हैं। हालांकि, हाल के दशकों में इज़राइली राजनीति में वामपंथ का प्रभाव काफी कम हुआ है।

पिछले कुछ दशकों में, इज़राइली राजनीति में लगातार दक्षिणपंथ की ओर झुकाव देखा गया है। दूसरे इंतिफादा की हिंसा, गाजा से एकतरफा वापसी के बाद हमास का उदय, और लगातार रॉकेट हमलों ने कई इज़राइलियों को यह विश्वास दिलाया है कि शांति के लिए कोई फिलिस्तीनी भागीदार नहीं है। इस माहौल ने बेंजामिन नेतन्याहू जैसे नेताओं को बढ़ावा दिया है, जिन्होंने ''संघर्ष प्रबंधन'' (Conflict Management) की नीति अपनाई है, न कि ''संघर्ष समाधान'' (Conflict Resolution) की।

4. आयरन डोम और तकनीकी श्रेष्ठता

इज़राइल की सुरक्षा रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक उसकी तकनीकी श्रेष्ठता है। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण आयरन डोम (Iron Dome) मिसाइल रक्षा प्रणाली है। राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स द्वारा विकसित, आयरन डोम को गाजा से दागे गए छोटे दूरी के रॉकेटों और मोर्टार को हवा में ही रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 2011 में अपनी तैनाती के बाद से, इसने हजारों रॉकेटों को सफलतापूर्वक रोका है और इज़राइली शहरों में हताहतों की संख्या को काफी कम कर दिया है।

आयरन डोम ने संघर्ष की गतिशीलता को बदल दिया है। इसने इज़राइल को हमास के रॉकेट हमलों के खिलाफ एक रक्षात्मक कवच प्रदान किया है, जिससे उसे सैन्य प्रतिक्रिया देने से पहले अधिक समय और लचीलापन मिलता है। हालांकि, आलोचकों का तर्क है कि आयरन डोम ने इज़राइली सरकार पर संघर्ष का स्थायी राजनीतिक समाधान खोजने के दबाव को भी कम कर दिया है। चूंकि इज़राइली नागरिक अपेक्षाकृत सुरक्षित महसूस करते हैं,

इसलिए कब्जे को समाप्त करने और एक स्थायी शांति समझौते पर पहुंचने की तत्काल आवश्यकता कम महसूस होती है। यह एक ष्तकनीकी समाधानष है, राजनीतिक नहीं, और यह संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित नहीं करता है।

संघर्ष के केंद्रीय मुद्दे

1. भूमि का प्रश्नः बस्तियाँ और सीमाएँ

संघर्ष के केंद्र में भूमि का प्रश्न है। 1967 के बाद से, इज़राइल ने वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में सैकड़ों बस्तियों (Settlements) का निर्माण किया है, जहाँ अब 700,000 से अधिक इज़राइली बसने वाले रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत, इन बस्तियों को अवैध माना जाता है क्योंकि वे कब्जे वाले क्षेत्र में नागरिकों को स्थानांतरित करने के खिलाफ चौथे जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन करती हैं।

ये बस्तियाँ एक व्यवहार्य और सन्निहित फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक हैं। वे वेस्ट बैंक को टुकड़ों में बांटती हैं, जिससे फिलिस्तीनियों के लिए आवाजाही मुश्किल हो जाती है और उनके आर्थिक जीवन में बाधा उत्पन्न होती है। फिलिस्तीनियों के लिए, ये बस्तियाँ इज़राइल की भूमि पर स्थायी नियंत्रण स्थापित करने की मंशा का प्रतीक हैं। इज़राइली दृष्टिकोण से, विशेष रूप से दक्षिणपंथियों के लिए, ये बस्तियाँ बाइबिल की भूमि पर यहूदी लोगों के ऐतिहासिक और धार्मिक अधिकार का दावा हैं। वे इन्हें सुरक्षा बफर के रूप में भी देखते हैं।

2. यरूशलेमः एक विभाजित शहर, एक संयुक्त दावा

यरूशलेम यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों, तीनों के लिए एक पवित्र शहर है। इसका दर्जा संघर्ष का सबसे भावनात्मक और विस्फोटक मुद्दा है। इज़राइल पूरे यरूशलेम को अपनी ''शाश्वत और अविभाजित राजधानी'' मानता है। 1980 में, उसने पूर्वी यरूशलेम पर कब्ज़ा कर लिया, एक ऐसा कदम जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा मान्यता नहीं दी गई है।

दूसरी ओर, फिलिस्तीनी पूर्वी यरूशलेम को अपने भविष्य के राज्य की राजधानी के रूप में देखते हैं। यहाँ अल–अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक स्थित हैं, जो इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। यहूदी धर्म का सबसे पवित्र स्थल, टेम्पल माउंट (जिसे मुसलमान हरम अल–शरीफ कहते हैं), भी यहीं स्थित है। इस पवित्र स्थल पर नियंत्रण और पूजा के अधिकारों को लेकर अक्सर तनाव और हिंसा भड़कती है। शेख जर्राह जैसे पूर्वी यरूशलेम के पड़ोस से फिलिस्तीनी परिवारों को बेदखल करने की धमकी जैसी घटनाओं ने हाल के वर्षों में बड़े संघर्षों को जन्म दिया है, जैसा कि 2021 में हुआ था।

3. शरणार्थियों की वापसी का अधिकार

1948 और 1967 के युद्धों में विस्थापित हुए फिलिस्तीनियों और उनके वंशजों, जिनकी संख्या अब लाखों में है, के लिए ''वापसी का अधिकार'' (Right of Return) एक मौलिक मांग है। वे संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 194 का हवाला देते हैं, जिसमें कहा गया है कि ''जो शरणार्थी अपने घरों में लौटना चाहते हैं और अपने पड़ोसियों के साथ शांति से रहना चाहते हैं, उन्हें जल्द से जल्द ऐसा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।''

यह फिलिस्तीनी राष्ट्रीय पहचान और नकबा की स्मृति का एक केंद्रीय तत्व है। हमास इस अधिकार पर कोई समझौता करने से इनकार करता है। इज़राइल के लिए, लाखों फिलिस्तीनी शरणार्थियों की वापसी को स्वीकार करना एक जनसांख्यिकीय खतरा है जो राज्य के यहूदी चरित्र को समाप्त कर देगा। इज़राइल का तर्क है कि शरणार्थियों को भविष्य के फिलिस्तीनी राज्य में बसाया जाना चाहिए, न कि इज़राइल में। यह मुद्दा शांति वार्ता में हमेशा एक दुर्गम बाधा रहा है।

4. फिलिस्तीनी नेतत्व का विभाजनः फतह बनाम हमास

फिलिस्तीनी पक्ष में आंतरिक विभाजन ने भी संघर्ष को जटिल बना दिया है। 2007 से, फिलिस्तीनी नेतृत्व दो मुख्य गुटों में बंटा हुआ हैः

- **फतह (Fatah)**: यासर अराफात द्वारा स्थापित यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी आंदोलन है, जो पीएलओ पर हावी

है और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी प्राधिकरण (Palestinian Authority - PA) का संचालन करता है। इसका नेतृत्व महमूद अब्बास करते हैं। फतह ने ओस्लो समझौते के माध्यम से इज़राइल के साथ बातचीत और दो–राज्य समाधान का रास्ता चुना है।

- **हमास (Hamas):** यह इस्लामी आंदोलन है जो गाजा पट्टी को नियंत्रित करता है और इज़राइल के साथ सशस्त्र प्रतिरोध की वकालत करता है।

यह विभाजन फिलिस्तीनियों को एक एकीकृत मोर्चे के रूप में बातचीत करने से रोकता है। इज़राइल अक्सर इस विभाजन का उपयोग यह तर्क देने के लिए करता है कि शांति के लिए कोई विश्वसनीय भागीदार नहीं है। जब इज़राइल फतह के साथ बातचीत करता है, तो हमास किसी भी समझौते को खारिज कर देता है। और जब वह हमास के साथ (अप्रत्यक्ष रूप से) संघर्ष विराम पर बातचीत करता है, तो यह फतह की वैधता को कमजोर करता है। मिस्र और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों द्वारा सुलह के कई प्रयास विफल रहे हैं, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच गहरा अविश्वास और वैचारिक मतभेद हैं।

अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय आयाम

1. संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिकाः एक मध्यस्थ या एक पक्ष?

संयुक्त राज्य अमेरिका ऐतिहासिक रूप से इज़राइल का सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है। यह इज़राइल को प्रति वर्ष अरबों डॉलर की सैन्य और आर्थिक सहायता प्रदान करता है और संयुक्त राष्ट्र में अक्सर इज़राइल को कूटनीतिक संरक्षण देता है, वीटो शक्ति का उपयोग करके उसके खिलाफ प्रस्तावों को रोकता है।

परंपरागत रूप से, अमेरिका ने इज़राइल–फिलिस्तीन संघर्ष में एक प्रमुख मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश की है। कैंप डेविड समझौते (1978) और ओस्लो समझौते (1993) अमेरिकी कूटनीति की सफलताएँ मानी जाती हैं। हालांकि, फिलिस्तीनियों और कई अन्य लोगों का मानना है कि अमेरिका एक ईमानदार मध्यस्थ नहीं है, क्योंकि उसका झुकाव स्पष्ट रूप से इज़राइल की ओर है।

डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन के दौरान यह झुकाव और भी स्पष्ट हो गया। ट्रम्प ने अमेरिकी दूतावास को तेल अवीव से यरूशलेम स्थानांतरित कर दिया, गोलान हाइट्स पर इज़राइली संप्रभुता को मान्यता दी, और एक शांति योजना प्रस्तावित की जिसे फिलिस्तीनियों ने पूरी तरह से इज़राइल के पक्ष में माना जो बिडेन के प्रशासन ने दो–राज्य समाधान के लिए पारंपरिक अमेरिकी समर्थन को बहाल किया है, लेकिन ट्रम्प के कई नीतिगत बदलावों को पलटा नहीं है। हमास के प्रति अमेरिका की नीति अडिग रही हैः वह इसे एक आतंकवादी संगठन मानता है और इसके साथ कोई सीधा संपर्क नहीं रखता है।

2. ईरान और प्रतिरोध की धुरी

ईरान हमास का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समर्थक है, जो उसे धन, हथियार और प्रशिक्षण प्रदान करता है। ईरान के लिए, हमास इज़राइल के खिलाफ उसके व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे वह ''प्रतिरोध की धुरी'' (Axis of Resistance) कहता है। इस धुरी में सीरिया में बशर अल–असद का शासन, लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूती विद्रोही भी शामिल हैं।

ईरान, एक शिया शक्ति के रूप में, सुन्नी हमास का समर्थन करके अपनी क्षेत्रीय पहुँच को प्रदर्शित करता है और अरब दुनिया में फिलिस्तीनी कारण के चौंपियन के रूप में खुद को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। ईरान का समर्थन हमास को इज़राइल के खिलाफ अपनी सैन्य क्षमताओं को बनाए रखने और सुधारने में मदद करता है, जिसमें लंबी दूरी के रॉकेटों का विकास भी शामिल है। यह समर्थन हमास को अरब देशों पर अपनी निर्भरता कम करने की भी अनुमति देता है।

3. मिस्र और कतर की दोहरी भूमिका

मिस्र और कतर, दोनों की हमास के साथ जटिल और महत्वपूर्ण भूमिकाएँ हैं:

- **मिस्र (Egypt):** मिस्र की गाजा के साथ एक महत्वपूर्ण सीमा (रफाह क्रॉसिंग) है, जो बाहरी दुनिया के लिए

गाजा का एकमात्र निकास द्वार है जिसे इज़राइल नियंत्रित नहीं करता है। मिस्र हमास के वैचारिक जनक, मुस्लिम ब्रदरहुड को एक घरेलू खतरे के रूप में देखता है, और इसलिए हमास के प्रति शंकालु है। हालांकि, मिस्र गाजा में स्थिरता बनाए रखने में भी रुचि रखता है ताकि हिंसा उसकी अपनी सीमाओं पर न फैले। इस वजह से, मिस्र अक्सर हमास और इज़राइल के बीच संघर्ष विराम और कैदियों की अदला–बदली की बातचीत में एक प्रमुख मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है।

- **कतर (Qatar):** कतर हमास का एक प्रमुख वित्तीय समर्थक रहा है। इसने गाजा के पुनर्निर्माण, सरकारी कर्मचारियों के वेतन और गरीब परिवारों को सहायता के लिए अरबों डॉलर प्रदान किए हैं। यह वित्तीय सहायता इज़राइल की मौन सहमति से दी गई है, क्योंकि इज़राइल का मानना है कि यह गाजा में एक पूर्ण मानवीय पतन को रोकने में मदद करता है, जो एक बड़े विस्फोट का कारण बन सकता है। कतर भी अक्सर एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, क्योंकि उसके हमास के राजनीतिक नेतृत्व के साथ घनिष्ठ संबंध हैं, जिनमें से कई दोहा में रहते हैं।

4. बदलते अरब–इज़राइल संबंधः अब्राहम समझौते

हाल के वर्षों में, मध्य पूर्व के भू–राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। 2020 में, अब्राहम समझौते (Abraham Accords) के तहत, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और बहरीन ने इज़राइल के साथ अपने संबंधों को सामान्य कर लिया, जिसके बाद सूडान और मोरक्को ने भी ऐसा ही किया।

इन समझौतों ने दशकों पुरानी अरब आम सहमति को तोड़ दिया कि इज़राइल के साथ संबंध तब तक सामान्य नहीं होंगे जब तक कि फिलिस्तीनी संघर्ष का समाधान नहीं हो जाता। इन अरब देशों ने ईरान को एक साझा खतरे के रूप में देखते हुए और आर्थिक और तकनीकी सहयोग के अवसरों को प्राथमिकता देते हुए, फिलिस्तीनी मुद्दे को दरकिनार कर दिया।

इन समझौतों ने फिलिस्तीनी नेतृत्व (फतह और हमास दोनों) को अलग–थलग और विश्वासघात महसूस कराया। हमास ने इन समझौतों की ''पीठ में छुरा घोंपने'' के रूप में निंदा की। हालांकि, इन समझौतों से यह भी पता चलता है कि फिलिस्तीनी कारण अब कई अरब शासनों के लिए केंद्रीय प्राथमिकता नहीं रह गया है, जो हमास और समग्र रूप से फिलिस्तीनी आंदोलन के लिए एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती है।

संघर्ष की प्रकृति और परिणाम

1. असममित युद्ध (Asymmetric Warfare)

हमास और इज़राइल के बीच का संघर्ष असममित युद्ध का एक क्लासिक उदाहरण है। एक तरफ इज़राइल है, जिसके पास दुनिया की सबसे उन्नत सेनाओं में से एक, एक मजबूत अर्थव्यवस्था और एक शक्तिशाली राष्ट्र–राज्य की सभी संरचनाएँ हैं। दूसरी तरफ हमास है, जो एक गैर–राज्य कर्ता है और पारंपरिक सैन्य साधनों से इज़राइल का मुकाबला नहीं कर सकता इसलिए, हमास गुरिल्ला रणनीति अपनाता है। इसका मुख्य हथियार रॉकेट हमला है। ये रॉकेट अक्सर अविष्कृत और गलत होते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य सैन्य लक्ष्यों को नष्ट करने से अधिक इज़राइली आबादी में भय और व्यवधान पैदा करना है। अन्य युक्तियों में सीमा पार सुरंगों का उपयोग, आत्मघाती हमले (मुख्य रूप से अतीत में), और सीमा पर विरोध प्रदर्शन शामिल हैं। हमास की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा मीडिया और सूचना युद्ध भी है, जिसका उद्देश्य वैश्विक जनमत को अपने पक्ष में करना है।

इज़राइल अपनी भारी सैन्य श्रेष्ठता का उपयोग करता है, जिसमें हवाई हमले, तोपखाने और जमीनी आक्रमण शामिल हैं। हालांकि, घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्र जैसे गाजा में लड़ना इज़राइल के लिए एक बड़ी चुनौती है। हमास जानबूझकर नागरिक क्षेत्रों से काम करता है, जो इज़राइल के लिए नागरिक हताहतों से बचना मुश्किल बना देता है। प्रत्येक नागरिक की मृत्यु, विशेष रूप से बच्चों की, इज़राइल के लिए एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पीआर क्षति होती है और हमास के आख्यान को मजबूत करती है कि वह एक क्रूर कब्जे वाले के खिलाफ लड़ रहा है।

2. मानवीय लागत

इस संघर्ष की सबसे बड़ी कीमत आम नागरिकों ने चुकाई है, विशेषकर गाजा में। बार–बार होने वाले युद्धों ने बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया है, घरों, अस्पतालों और स्कूलों को मलबे में बदल दिया है। नाकाबंदी ने अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है, जिससे गरीबी और निराशा बढ़ी है। गाजा में युवा पीढ़ी युद्ध और अभाव के माहौल में बड़ी हुई है, जिससे व्यापक मनोवैज्ञानिक आघात पहुंचा है।

इज़राइली पक्ष में, हालांकि हताहतों की संख्या बहुत कम है (मुख्य रूप से आयरन डोम के कारण), लेकिन दक्षिण इज़राइल में रहने वाले समुदायों को लगातार रॉकेट हमलों के सायरन और आश्रयों में भागने के आघात का सामना करना पड़ता है। यह निरंतर तनाव नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ता है।

3. कानूनी और नैतिक बहसें

संघर्ष ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और युद्ध की नैतिकता पर गंभीर बहसें छेड़ दी हैं। इज़राइल पर गाजा में अपने सैन्य अभियानों के दौरान आनुपातिकता (Proportionality) के सिद्धांत का उल्लंघन करने और अंधाधुंध हमले करने का आरोप लगाया गया है। वेस्ट बैंक में उसकी बस्ती नीति और गाजा की नाकाबंदी को व्यापक रूप से अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) ने इन संभावित युद्ध अपराधों की जांच शुरू की है।

हमास पर भी युद्ध अपराधों का आरोप लगाया गया है, विशेष रूप से इज़राइली नागरिक केंद्रों पर अंधाधुंध रॉकेट दागने के लिए। नागरिक क्षेत्रों से सैन्य अभियान संचालित करने की उसकी रणनीति भी अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन करती है।

निष्कर्ष और भविष्य के परिदृश्य

1. एक स्थायी गतिरोध

हमास और इज़राइल के बीच का संघर्ष एक स्थायी गतिरोध की स्थिति में पहुँच गया प्रतीत होता है। दोनों पक्षों के अधिकतमवादी लक्ष्य एक–दूसरे के साथ सीधे विरोधाभास में हैं। हमास, अपनी मूल विचारधारा के अनुसार, इज़राइल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर सकता। इज़राइल, अपनी सुरक्षा चिंताओं के कारण, अपनी सीमाओं पर एक सशस्त्र इस्लामी समूह को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो उसके विनाश के लिए प्रतिबद्ध है।

शांति प्रक्रिया, जैसी कि ओस्लो समझौते में कल्पना की गई थी, लगभग मृत है। दो–राज्य समाधान, जो कभी अंतर्राष्ट्रीय सहमति का आधार था, अब पहले से कहीं अधिक दूर की कौड़ी लगता है। वेस्ट बैंक में बस्तियों के निरंतर विस्तार ने एक व्यवहार्य फिलिस्तीनी राज्य के लिए भूमि को लगभग समाप्त कर दिया है। फिलिस्तीनी नेतृत्व का विभाजन और इज़राइली राजनीति का दक्षिणपंथ की ओर झुकाव इस गतिरोध को और गहरा करता है।

2. संभावित भविष्य के परिदृश्य

आगे देखते हुए, कई संभावित परिदृश्य कल्पना योग्य हैं:

1. **यथास्थिति का कायम रहना (Status Quo)**: यह सबसे संभावित परिदृश्य है। इसमें ''संघर्ष प्रबंधन'' की नीति जारी रहेगी, जिसमें समय–समय पर हिंसा भड़कती रहेगी, जिसके बाद अस्थिर संघर्ष विराम होंगे। इज़राइल गाजा की नाकाबंदी बनाए रखेगा और हमास की सैन्य क्षमताओं को ''काटने'' के लिए आवधिक अभियान चलाएगा। हमास गाजा पर अपना नियंत्रण बनाए रखेगा और प्रतिरोध जारी रखेगा। मानवीय पीड़ा जारी रहेगी।
2. **एक–राज्य वास्तविकता (One-State Reality)**: दो–राज्य समाधान की विफलता के साथ, कई विश्लेषक तर्क देते हैं कि क्षेत्र प्रभावी रूप से एक–राज्य वास्तविकता की ओर बढ़ रहा है, जिसमें इज़राइल जॉर्डन नदी और भूमध्य सागर के बीच की पूरी भूमि को नियंत्रित करता है। यह एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है; यह किस तरह का राज्य होगा? क्या यह एक रंगभेदी (Apartheid) राज्य होगा, जहाँ यहूदियों को पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे और फिलिस्तीनियों को कम अधिकार? या क्या यह एक द्वि–राष्ट्रीय (bi-national) राज्य

होगा, जहाँ दोनों लोगों को समान अधिकार होंगे, जो इज़राइल के यहूदी राज्य होने के विचार को चुनौती देगा

3. **दीर्घकालिक संघर्ष विराम (Hudna):** कुछ लोगों का प्रस्ताव है कि एक स्थायी शांति समझौते के बजाय, एक दीर्घकालिक संघर्ष विराम या हुदना (Hudna) एक अधिक यथार्थवादी लक्ष्य हो सकता है। यह एक इस्लामी अवधारणा है जो एक अस्थायी शांति को संदर्भित करती है। एक हुदना के तहत, हमास वर्षों या दशकों तक इज़राइल पर हमले रोकने के लिए सहमत हो सकता है, जिसके बदले में इज़राइल नाकाबंदी को समाप्त कर देगा और गाजा के पुनर्निर्माण की अनुमति देगा। यह संघर्ष का समाधान नहीं करेगा, लेकिन यह हिंसा को कम कर सकता है और जीवन को बेहतर बना सकता है।
4. **हमास का पतन या परिवर्तन:** यह संभव है कि आंतरिक दबाव, शासन की विफलता, या एक बड़े सैन्य टकराव के परिणामस्वरूप गाजा में हमास का शासन समाप्त हो जाए। वैकल्पिक रूप से, हमास अपनी विचारधारा को और नरम कर सकता है, इज़राइल के अस्तित्व को स्वीकार कर सकता है और पीएलओ की तरह एक मुख्यधारा के राजनीतिक आंदोलन में बदल सकता है। हालांकि, वर्तमान में इन दोनों ही परिणामों की संभावना कम लगती है।

3. अंतिम विचार: संतुलन की असंभव खोज

''हमास बनाम इज़राइल: एक अंतहीन टकराव या भू–राजनीतिक संतुलन की खोज?'' यह शीर्षक ही संघर्ष के मूल द्वंद्व को दर्शाता है। एक ओर, यह एक अंतहीन चक्र प्रतीत होता है, जो ऐतिहासिक शिकायतों, वैचारिक कठोरता और पारस्परिक अविश्वास से प्रेरित है। दूसरी ओर, दोनों पक्ष, अपने–अपने तरीकों से, एक ऐसे संतुलन की तलाश में हैं जो उनके अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके।

हमास के लिए, यह संतुलन प्रतिरोध और शासन के बीच है। इज़राइल के लिए, यह संतुलन सुरक्षा और लोकतंत्र के बीच है। अब तक, किसी भी पक्ष को एक स्थायी संतुलन नहीं मिला है। स्थायी शांति के लिए एक गहन परिवर्तन की आवश्यकता होगी, नेतृत्व में परिवर्तन, आख्यानों में परिवर्तन, और सबसे महत्वपूर्ण, कब्जे को समाप्त करने और फिलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता देने की इच्छा। जब तक ऐसा नहीं होता, हमास और इज़राइल के बीच का संघर्ष मध्य पूर्व और दुनिया के लिए एक खुला घाव बना रहेगा, जो अस्मिता, भूमि और शक्ति की एक दुखद और हिंसक कहानी बयान करता रहेगा।

संदर्भ सूची

1. Analysis from the International Crisis Group, Council on Foreign Relations, and other think tanks. https://www.crisisgroup.org/crisiswatch, Accessed on 15/05/2025.
2. Chehab, Z. (2007) *Inside Hamas: The Untold Story of the Militant Islamic Movement*. I.B. Tauris.
3. Hamas Covenant (1988) https://www.wilsoncenter.org/article/doctrine-hamas, Accessed on 18/05/2025.
4. Hamas: A Document of General Principles and Policies (2017). https://irp.fas.org/world/para/docs/880818a.html, Accessed on 20/05/2025.
5. Mishal, S.; & Sela, A. (2006) *The Palestinian Hamas: Vision, Violence, and Coexistence*, Columbia University Press, Columbia.
6. Khalidi, R. (2020) The Hundred Years' War on Palestine: A History of Settler Colonialism and Resistance, 1917–2017, Metropolitan Books, *Journal Indexed in Emerging Sources* Citation Index (Web of Science) Covered in Clarivate Analytics products and services, ISSN: 0018-1005, LV(1), 501-505.

7. Reports from Human Rights Watch, Amnesty International, and B'Tselem, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2025/07/israel-opt-israeli-organizations-conclude-israel-committing-genocide-against-palestinians-in-gaza-in-another-milestone-for-accountability-efforts, Accessed on 12/05/2025.

8. Sayigh, Y. (2015) *The Gaza Strip: A Political Economy of De-development*. The Carnegie Endowment for International Peace, https://dokumen.pub/the-gaza-strip-the-political-economy-of-de-development-0887282601-088728261x.html UNIVERSITY OF MICHIGAN, Accessed on 21/05/2025.

9. Shlaim, A. (2014) *The Iron Wall: Israel and the Arab World*. W. W. Norton & Company. London: Penguin

10. The Balfour Declaration (1917). https://www.britannica.com/event/Balfour-Declaration, Accessed on 12/05/2025,

11. UN General Assembly Resolution 181 (1947) https://www.un.org/unispal/data-collection/general-assembly/, Accessed on 05/05/2025.

12. UN Security Council Resolution 242 (1967) https://digitallibrary.un.org/record/90717?ln=en&v=pdf, Accessed on 14/05/2025.

****